1		2	3	4	5
16	Sikkim (at 1982 prices)	9 41	4 66	15 07	11 31
17	Tamil Nadu .	. (—)11 64	17 04(—)	5 77	4 53
18	Tripura .	8 11	N A	N.A	4 10
19	Uttar Pradesh	. 23 30	1 87	9 06	4 78
20	West Bengal	. 11 07(—)	4 00(—)	1 69	15 62
	Union Territories				
21	Arunachal Pradesh	6 04	16 58	9 98	3 09
22	Delhi	2 70	5 98	8 30	6 05
23	Goa, Daman & Diu	16 48(—)	1 78	8 04	6 26
24	Pondicherry . . .	4 08	8 48	0 82(—)	1 50

N A Not Available (The figures have not been supplied by the concerned State Governments)

NOTE 1 Owing to differences in methodology and source material used, the figures for different States are not strictly comparable

NOTE 2 The States of Meghalaya and Nagaland prepare these estimates at current prices only.

NOTE 3 The Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep and Mizoram do not prepare these estimates

SOURCE Directorate of Economics & Statistics for estimates

Death in police custody

2250. SHRI TALARI MANOHAR Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether attention of the Government have been drawn to the news item which appeared in Times of India dated 26th October, 1986 regarding death in Police custody and if so, the details thereof, and

(b) whether it is a fact that All India Institute of Medical Sciences Doctors are being pressurised to alter post mortem report and if so, whether a separate magisterial inquiry is likely to be made in such serious allegations above?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir. Chowkidar Dayal Singh, a suspect in a theft case, was arrested and he died in police custody Inquest proceedings are being conducted. The Inquesting Magistrate has sought the opinion of a Board of three Doctors, one each from All India Institute of Medical Sciences, Lady Hardinge Medical College and University College of Medicine regarding the cause of the death Sub-Inspector Ranbir Singh in whose custody Dayal Singh had died, has been placed under suspension

(b) No, Sir

गरीबी दूर करने की योजना

2251 **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में इस समय कौन-कौन सी गरीबी दूर करने की योजनाएं चल रही हैं तथा ये कब से चल रही हैं; और

(ख) इन योजनाओ के क्रियान्वयन का ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय देश मे तीन प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमे चल रही हैं जिनका उद्देश्य गरीबी दूर करना है। य हैं— एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1978–79 मे 2300 ब्लाको मे शुरू किया गया था और 2 अक्तूबर, 1980 से इसे देश के सभी शेष ब्लाको मे भी शुरू कर दिया गया। 2 अक्तूबर, 1980 से पहले के "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त शहरी गरीब वर्ग के लिए एक स्व-रोजगार स्कीम भी 1 सितम्बर, 1986 से प्रारभ की गई।

(ख) इन स्कीमो के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं.

1 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम मे राज्य सहायता और ऋण के जरिए उत्पादनकारी परिसपत्तियों तथा निदेशों को व्यवस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को स्व-रोजगार-अवसर देने में सहायता की जाती है। आर्थिक सहायता मे केन्द्र और राज्यो की समान सहभागिता होती है। छठी योजना तथा 1985–86 के दौरान सहायता प्राप्त लाभभोगी परिवारो की संख्या क्रमश. 16 56 मिलियन तथा 3 02 मिलियन थी।

2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ-कारी रोजगार का सृजन, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन तथा लोगो के जीवन स्तर तथा पोषाहार स्थिति में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में भी केन्द्र तथा राज्यो द्वारा 50:50 के अनुपात में धन लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छठी योजना तथा 1985–86 के दौरान सृजित रोजगार क्रमश: 1775.18 मिलियन श्रम दिवस तथा 316.05 मिलियन श्रम दिवस था।

3 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष मे 100 दिवस तक कम से कंम हर भूमिहीन श्रमिक परिवार के एक सदस्य को रोजगार गारटी प्रदान करने की दृष्टि से ग्रामीण भूमिहीनो के लिये रोजगार के अवसर को बढाना और उनमे सुधार करना तथा आधार सरचना को सुदृढ़ करके स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियो का सृजन करना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढती हुई मागो की पूर्ति हो सके। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा धन की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। छठी योजना और 1985–86 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित रोजगार क्रमश 262 75 मिलियन श्रम दिवस तथा 231.88 मिलियन श्रम दिवस था।

4 शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार स्कीम

इस स्कीम के अतर्गत शहरी गरीब जैसे रिक्शावाले, मोची, फेरीवाले, सब्जी व फल विक्रेताओ को सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अतर्गत, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर कोई भी पात्र ऋणी 5000 रु० का ऋण ले सकता है। केन्द्र सरकार इसके लिए 25 प्रतिशत की राज सहायता देती है। चालू वर्ष के दौरान इसके अतर्गत 5 लाख लाभग्राहियो को इसमे शामिल करने का प्रस्ताव है।

Dividend by Central Government Employees' Consumer Cooperative Society

2252. SHRIMATI RATAN KUMARI Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government Employees' Consu-